राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5457 / 2022

ओम प्रकाश मीणा (कर्मचारी आई.डी.–आरजेबीपी199207019863)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2022
आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि. विभाग ग्रामीण खंड डीग के आदेश क्रमांक 1778–1745 दिनांक 27.06.1995 के द्वारा बेलदार के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित किया गया था तथा अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास थी। किंतु श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि. विभाग ग्रामीण खंड डीग के आदेश क्रमांक 5881–5972 दिनांक 07.11.1996 के आदेश द्वारा आठवीं पास बेलदारों को सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान दी गई थी तथा सहायक का वेतनमान दिया गया तथा अपीलार्थी को सहायक के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई थी। अपीलार्थी के साथ के अन्य बेलदारों को सहायक के पद पर नियुक्ति किया गया था। अतः अपीलार्थी अद्धस्थायी से सहायक का वेतनमान पाने का अधिकारी है। समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 16.12.1994 सी.डब्ल्यू. 3648 / 89 द्वारा लाभ दिया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)